Exchange rate and IMF's Exchange Rate Regime Classification

विनिमय दर और IMF की विनिमय दर व्यवस्था वर्गीकरण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी भारत पर वार्षिक स्टाफ रिपोर्ट में भारत के वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को "स्थिर व्यवस्था" से बदलकर "क्रॉल-लाइक व्यवस्था" के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है।

विनमय दर क्या है ?

विनिमय दर वह मूल्य है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है।

उदाहरण: ₹88 प्रति USD का अर्थ है — 1 अमेरिकी डॉलर = 88 भारतीय रुपये।

विनिमय दर प्रणालियों के प्रकार

1. स्थिर विनिमय दर प्रणाली

- सरकार/केंद्रीय बैंक किसी मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा के मुकाबले निर्धारित करता है।
- इस तय दर को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक लगातार विदेशी मुद्रा खरीदता/बेचता है।
- उद्देश्य: विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना।

2. परिवर्तनीय/तैरती विनिमय दर प्रणाली

- विनिमय दर पूरी तरह बाज़ार की मांग और आपूर्ति से तय होती है।
- केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

3. प्रबंधित तैरती विनिमय दर

- विनिमय दर मुख्यतः बाज़ार द्वारा निर्धारित होती है।
- लेकिन केंद्रीय बैंक अत्यधिक उतार-चढ़ाव नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करता है।
- यह प्रणाली भारत सहित कई देशों में प्रचलित है।

4. पेग्ड विनिमय दर प्रणाली

- मुद्रा को किसी एक मुद्रा या मुद्राओं की टोकरी से बांध दिया जाता है ।
- उदाहरण: कुछ खाड़ी देश अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से पेग करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सदस्य देशों की विनिमय दर व्यवस्था का वर्गीकरण वास्तविक (de facto) व्यवहार के आधार पर करता है—यानी मुद्रा वास्तव में कैसे चलती है, न कि सरकार क्या दावा करती है।

IMF की प्रणाली में कुल 10 श्रेणियाँ होती हैं, जिन्हें निम्न समूहों में बाँटा गया है:

- हार्ड पेग्स (Hard Pegs)
- सॉफ्ट पेग्स (Soft Pegs)
- फ्लोटिंग व्यवस्थाएँ (Floating Regimes)
- अन्य (Others)

In news: The IMF, in its annual staff report on India, has **reclassified India's de facto exchange rate regime** from *"stabilised arrangement"* to a *"crawl-like arrangement"*.

WHAT IS AN EXCHANGE RATE?

The **exchange rate** is the price of one currency expressed in terms of another.

Example: **₹88 per USD** means 1 US Dollar = 88 Indian Rupees.

Types of Exchange Rate systems

1. **Fixed Exchange Rate System:** The government/central bank **fixes the value of the currency** against another currency. Central bank continuously buys/sells foreign currency to maintain the fixed rate.
   It is used to maintain stability.
2. **Floating Exchange Rate System:** Exchange rate is **fully determined by market demand & supply**\ and there is **no central bank intervention**.
3. **Managed Floating Exchange rate system:** Exchange rate is mostly **market-determined**, but the **central bank intervenes** to control **undue volatility**.
4. **Pegged Exchange rate system: when** Currency is **tied (pegged)** to **One currency** or a **basket of currencies**,

IMF's EXCHANGE RATE REGIME CLASSIFICATION

1. The **International Monetary Fund (IMF)** classifies every member country's exchange rate regime **based on de facto behaviour**—i.e., how the currency *actually* moves, not what the government *claims*.
2. This system has **10 categories**, grouped under **Hard Pegs, Soft Pegs, Floating Regimes, and Others**.

I. हार्ड पेग्स

1. नो सेपरेट लीगल टेंडर देश अपनी स्वयं की मुद्रा के बजाय किसी अन्य देश की मुद्रा का उपयोग करता है।उदाहरण: इक्वाडोर (USD), कोसोवो (Euro)

2. करेंसी बोर्ड व्यवस्था (Currency Board Arrangement)
   - विनिमय दर पूरी तरह स्थिर।
   - 100% विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा समर्थित।उदाहरण: हांगकांग

II. सॉफ्ट पेग्स

स्थिर विनिमय दर, लेकिन कुछ लचीलेपन के साथ।

1. पारंपरिक पेग मुद्रा किसी अन्य मुद्रा या मुद्राओं की टोकरी से सीमित दायरे में पेग की जाती है।उदाहरण: सऊदी रियाल—USD से पेग

2. स्थिर व्यवस्था विनिमय दर 6 महीनों तक ±2% बैंड के भीतर रहती है।IMF के अनुसार 2024 तक भारत इसी श्रेणी में था।

3. क्रॉल-लाइक व्यवस्था
   - विनिमय दर एक पूर्वानुमेय, छोटे-छोटे कदमों (crawl) में चलती है—जैसे धीरे-धीरे अवमूल्यन या मूल्यवृद्धि।

4. IMF ने हाल ही में भारत को इस श्रेणी में रखा है, क्योंकि INR का धीमा, नियंत्रित अवमूल्यन देखा गया।

5. क्रॉलिंग पेग पेग स्वयं ही नियत अंतरालों पर नियमित रूप से समायोजित किया जाता है।

6. बैंड्स के भीतर पेग (Pegged Within Bands)विनिमय दर चौड़े बैंड (±5% या अधिक) के भीतर उतार-चढ़ाव कर सकती है।

III. फ्लोटिंग व्यवस्थाएँ

अधिक लचीलापन, कम केंद्रीय बैंक नियंत्रण।

1. फ्लोटिंग (Floating)बाज़ार द्वारा दर तय होती है; केंद्रीय बैंक केवल आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करता है।

2. फ्री फ्लोट (Free Float) कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं—पूरी तरह बाज़ार-निर्धारित।उदाहरण: अमेरिका, यूरोज़ोन

IV. अवशिष्ट श्रेणी (Residual Category)

अन्य प्रबंधित व्यवस्था (Other Managed Arrangement)केंद्रीय बैंक का प्रमुख हस्तक्षेप होता है, लेकिन स्पष्ट पेग या क्रॉल नहीं होता।

IMF क्लासिफिकेशन में भारत की जगह

1. ऑफिशियल (डी ज्यूर) – RBI के अनुसार
2. भारत का एक्सचेंज रेट मार्केट से तय होता है, और RBI सिर्फ़ वोलैटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए दखल देता है। इसलिए ऑफिशियली, भारत का दावा है: मैनेज्ड फ्लोटिंग
3. IMF (डी फैक्टो) – असल एक्सचेंज रेट मूवमेंट के आधार पर

I. Hard Pegs

1. **No Separate Legal Tender:** Country uses another country's currency. Eg: Ecuador (USD), Kosovo (Euro).
2. **Currency Board Arrangement:** Fixed exchange rate backed by **100% foreign reserve cover**. Eg: Hong Kong.

II. Soft Pegs

Characterised by a **fixed rate**, but with some flexibility.

1. **Conventional Peg:** Currency pegged to another currency or basket with **limited band**. Eg: Saudi riyal to USD.
2. **Stabilised Arrangement:** Exchange rate stays within **±2% band for 6 months. India was in this category (as per IMF) until 2024.**
3. **Crawl-Like Arrangement:** Exchange rate follows a **predictable, small-step (crawl) movement**, usually depreciation or appreciation at a **pre-announced rate or trend**.
4. **IMF recently placed India here** due to gradual, controlled INR depreciation.
5. **Crawling Peg:** The peg itself is adjusted periodically at fixed, known intervals.
6. **Pegged Within Bands:** Exchange rate allowed to fluctuate within **wider bands (±5% or more)**.

III. Floating Regimes

More flexibility, less central bank control.

1. **Floating:**Market determines exchange rate with intervention when required.
2. **Free Float:** No government intervention. Purely market-determined. Eg: US, Eurozone.

IV. Residual Category

Other Managed Arrangement: Significant central bank intervention but without a clear peg or crawl.

India's Position in IMF Classification

1. Official (De jure) – as per RBI
2. India has a market-determined exchange rate, and RBI intervenes only to control volatility.So officially, India claims: Managed Floating
3. IMF (De facto) – based on actual exchange rate movement

अलग-अलग सालों में, IMF ने भारत को इस तरह क्लासिफाई किया है:

1. स्टेबिलाइज्ड अरेंजमेंट (पहले का समय)

- एक्सचेंज रेट एक छोटे दायरे में रहा
- रुपये में महीने-दर-महीने सीमित बदलाव दिखा
- इसलिए, IMF का मानना था कि भारत रुपये को एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास स्टेबल कर रहा है

2. क्रॉल-लाइक अरेंजमेंट (हाल का क्लासिफिकेशन)

IMF ने देखा कि:

- रुपये में धीमा, अंदाज़ा लगाया जा सकने वाला डेप्रिसिएशन ट्रेंड दिखता है
- मूवमेंट छोटे, लगातार और डायरेक्शनल होते हैं
- यह एक "क्रॉलिंग" एक्सचेंज रेट जैसा दिखता है, भले ही भारत किसी क्रॉल की घोषणा नहीं करता है

IMF ने भारत को "क्रॉल-लाइक" क्यों बताया?

IMF असली डेटा देखता है, RBI की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। भारत ने दिखाया:

1. धीरे-धीरे डेप्रिसिएशन ट्रेंड: INR सात महीनों (मार्च-अक्टूबर 2025) में 3.5% कमजोर हुआ। वोलाटाइल नहीं, बल्कि स्मूद और स्थिर।
2. नैरो ट्रेडिंग बैंड: अक्टूबर में ₹87.8–88.8 प्रति USD कम वोलैटिलिटी। छोटे बदलावों वाले ऐसे टाइट बैंड "क्रॉल" जैसे दिखते हैं।
3. रेगुलर RBI FX इंटरवेंशन
   - FY25: RBI ने लगभग $400 बिलियन बेचे।
   - H1 FY26: RBI ने $44.3 बिलियन बेचे।
   - यह पैटर्न फ्री फ्लोट के बजाय कंट्रोल्ड मूवमेंट को बनाता है।

क्लासिफिकेशन के मतलब

- बाहरी सेक्टर की स्टेबिलिटी दिखाता है।
- एक्सचेंज रेट को स्मूद करने में RBI की भूमिका पर रोशनी डालता है।
- यह हल्के दखल का संकेत है, मैनिपुलेशन का नहीं।
- विदेशी इन्वेस्टर की सोच पर असर डाल सकता है।

भारत इससे सहमत क्यों नहीं है?

RBI का कहना है:

- एक्सचेंज रेट मार्केट तय करता है
- दखल सिर्फ़ वोलैटिलिटी कंट्रोल के लिए है
- कोई पहले से तय टारगेट नहीं है
- कोई क्रॉल अनाउंस नहीं किया गया है
- रुपये को किसी भी वैल्यू के आस-पास स्टेबल रखने का कोई कमिटमेंट नहीं है

इसलिए भारत किसी छिपे हुए पेग या क्रॉल के अंदाज़े को खारिज करता है।

Over different years, the IMF has classified India as:

1. Stabilised Arrangement (earlier period)

- Exchange rate remained within a narrow band
- Rupee showed limited month-to-month variability
- Therefore, IMF believed India was stabilising the rupee around a central value

2. Crawl-Like Arrangement (recent classification)

IMF observed that:

- The rupee shows a slow, predictable depreciation trend
- Movements are small, persistent, and directional
- This resembles a "crawling" exchange rate, even though India does not announce any crawl

WHY DID IMF CLASSIFY INDIA AS "CRAWL-LIKE"?

IMF looks at actual data, not RBI's official policy. India showed:

1. **Gradual Depreciation Trend:** INR weakened 3.5% over seven months (Mar–Oct 2025). Not volatile, but smooth and steady.
2. **Narrow Trading Band:** ₹87.8–88.8 per USD in October low volatility. Such tight bands with small shifts resemble a "crawl".
3. **Regular RBI FX Intervention**
   - FY25: RBI sold nearly $400 billion.
   - H1 FY26: RBI sold $44.3 billion.
   - This pattern shapes controlled movement rather than free float.

Implications of classification

- Shows external sector stability.
- Highlights RBI's role in exchange rate smoothing.
- Signals moderate intervention, not manipulation.
- Can affect foreign investor perception.

Why does India disagree?

RBI says:

- Exchange rate is market-determined
- Interventions are only for volatility control
- No predetermined target
- No crawl announced
- No commitment to keep the rupee stable around any value

Hence India rejects the inference of a hidden peg or crawl.

INS Mahe

India's New Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC)

INS माहे – भारत का नया एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC)

1. भारत के पास 7,516 km का एक बड़ा कोस्टलाइन है, जिसमें 12 बड़े पोर्ट, 184 छोटे पोर्ट और 1,197 आइलैंड टेरिटरी हैं। यह बड़ा समुद्री भूगोल कोस्टल सर्विलांस और एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) को एक ज़रूरी सिक्योरिटी प्रायोरिटी बनाता है।
2. INS माहे, इंडियन नेवी में शामिल किए जा रहे आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) में से पहला वेसल है। खास तौर पर लिटोरल वारफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया यह क्राफ्ट, इंडियन ओशन रीजन (IOR) में बढ़ते अंडरसी खतरों के समय भारत के कोस्टल डिफेंस ग्रिड को मज़बूत करता है।

इंडिजिनल डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा इंडिजिनसली डिज़ाइन और बनाया गया।
- 90% से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट, जो डिफेंस शिपबिल्डिंग में आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के कदम को दिखाता है।
- BEL, L&T डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, NPOL और कई MSMEs जैसे बड़े घरेलू पार्टनर्स का शामिल होना।

ऑपरेशनल भूमिकाएँ

- कम गहरे पानी में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW)
- पानी के नीचे निगरानी
- सर्च और रेस्क्यू (SAR)
- कम इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन्स (LIMO)
- माइन-लेइंग
- तटीय काफिलों के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी
- हार्बर डिफेंस

ये मिशन भारत के कम गहरे पानी वाले ASW ग्रिड में लंबे समय से मौजूद क्षमता की कमी को पूरा करते हैं।

INS Mahe – India's New Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC)

1. India possesses a vast coastline of 7,516 km, with 12 major ports, 184 minor ports, and 1,197 island territories. This extensive maritime geography makes coastal surveillance and Anti-Submarine Warfare (ASW) a critical security priority.
2. INS Mahe is the first vessel of the eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC) being inducted by the Indian Navy. Designed specifically for littoral warfare, the craft strengthens India's coastal defence grid at a time of rising undersea threats in the Indian Ocean Region (IOR).

Indigenous Design and Construction

- Indigenously designed and built by Cochin Shipyard Limited (CSL).
- Over 90% indigenous components, reflecting India's push toward Aatmanirbhar Bharat in defence shipbuilding.
- Involvement of major domestic partners such as BEL, L&T Defence, Mahindra Defence Systems, NPOL and several MSMEs.

Intended Operational Roles

- Anti-Submarine Warfare (ASW) in shallow waters
- Underwater surveillance
- Search and Rescue (SAR)
- Low Intensity Maritime Operations (LIMO)
- Mine-laying
- Escort duties for coastal convoys
- Harbour defence

These missions address a long-standing capability gap in India's shallow-water ASW grid.

खास बातें और काबिलियत

a) डिज़ाइन और साइज़

- लंबाई: 78 मीटर
- डीज़ल इंजन-वॉटरजेट प्रोपल्शन सिस्टम से चलने वाला सबसे बड़ा भारतीय नेवी का वॉरशिप।
- कम गहराई की वजह से तटीय और नदी के मुहाने के पानी में मैनूवरेबिलिटी मुमकिन होती है।

b) प्रोपल्शन के फायदे

- वॉटरजेट प्रोपल्शन ये देता है:
  - o बेहतर मैनूवरेबिलिटी
  - o कम अकूस्टिक सिग्नेचर ASW ऑपरेशन के लिए ज़रूरी जहाँ स्टेल्थ ज़रूरी है
  - o बड़े फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर की पहुँच से दूर इलाकों में ऑपरेट करने की काबिलियत

c) हथियार और सेंसर

- RBU-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर
- हल्के टॉरपीडो-ट्यूब लॉन्चर के दो सेट
- स्टेल्थी सबमरीन का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एडवांस्ड सोनार सिस्टम
- मॉडर्न कम्युनिकेशन और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम

ये सिस्टम कम गहरे पानी में सब-सरफेस खतरों का असरदार तरीके से पता लगाने, उन्हें क्लासिफ़ाई करने और उन्हें बेअसर करने में मदद करते हैं।

d) फुर्ती और मिशन में लचीलापन

- तेज़ फुर्ती और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, तटीय लड़ाई और बंदरगाह के रास्तों में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं।
- तटीय समुद्री रास्तों पर पेट्रोलिंग और उन्हें साफ़ करने के लिए यह बहुत अच्छा है, जो भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

रणनीतिक महत्व

- भारत के लेयर वाले तटीय रक्षा ढांचे को बेहतर बनाता है।
- भारतीय तट के पास चुपके से चलने वाली डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की चुनौती का समाधान करता है।
- बड़े सतही लड़ाकू विमानों को ब्लू-वॉटर ऑपरेशन के लिए आज़ाद करता है।
- मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) पहलों को सपोर्ट करता है और P-8I एयरक्राफ्ट और MH-60R हेलीकॉप्टर जैसे एसेट्स को पूरा करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की क्षमता को मज़बूत करता है और रोकथाम में मदद करता है।

लिटोरल ASW कैपेबिलिटी क्यों ज़रूरी है

a) तट के पास छिपकर चलने वाली सबमरीन का खतरा

- डीज़ल-इलेक्ट्रिक सबमरीन किनारे के पास कम गहरे पानी में चुपचाप चलती हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- बड़े वॉरशिप ऐसे पानी में ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे तट के पास कमज़ोरी पैदा होती है।

b) ज़रूरी समुद्री एसेट्स की सुरक्षा

भारतीय तटवर्ती इलाकों में ये हैं:

- हार्बर अप्रोच
- बड़े पोर्ट्स के लिए सी-लेन
- ऑफशोर एनर्जी एसेट्स
- ऑपरेशनल नेवल बेस

Key Features and Capabilities

a) Design and Dimensions

- Length: **78 metres**
- Largest Indian naval warship powered by a **diesel engine–waterjet propulsion system**.
- **Shallow draught** enables manoeuvrability in coastal and estuarine waters.

b) Propulsion Advantages

- Waterjet propulsion provides:
  - o **Superior manoeuvrability**
  - o **Reduced acoustic signature** → crucial for ASW operations where stealth is vital
  - o Ability to operate in areas inaccessible to larger frigates and destroyers

c) Weapons and Sensors

- **RBU-6000 anti-submarine rocket launcher**
- **Two sets of lightweight torpedo-tube launchers**
- Advanced sonar systems for detection and tracking of stealthy submarines
- Modern communication and combat management systems

These systems allow effective detection, classification, and neutralisation of sub-surface threats in shallow waters.

d) Agility and Mission Flexibility

- High agility and compact design enhance performance in **littoral combat** and **harbour approaches**.
- Ideal for patrolling and sanitising coastal sea lanes that are critical for India's economic security.

Strategic Significance

- Enhances India's **layered coastal defence architecture**.
- Addresses the challenge of stealthy diesel-electric submarines operating close to the Indian coastline.
- Frees larger surface combatants for **blue-water operations**.
- Supports Maritime Domain Awareness (MDA) initiatives and complements assets like P-8I aircraft and MH-60R helicopters.
- Strengthens naval capability in the Indian Ocean Region and contributes to **deterrence**.

Why Littoral ASW Capability Is Critical

a) Threat of stealthy submarines near the coast

- Diesel-electric submarines operate silently in shallow, near-shore waters, making detection difficult.
- Larger warships cannot manoeuvre effectively in such waters, creating vulnerability close to the coastline.

b) Protection of vital maritime assets

The Indian littorals house:

- Harbour approaches
- Sea-lanes to major ports
- Offshore energy assets
- Operational naval bases

India-Nepal Border Dispute

हाल का मामला

- नवंबर 2025 में, नेपाल की सरकार ने अपने अपडेटेड पॉलिटिकल मैप वाले 100 रुपये के करेंसी नोट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के कंट्रोल वाले इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा शामिल हैं।
- नए नोट में ये चीज़ें हैं:
  - o बाईं ओर माउंट एवरेस्ट
  - o दाईं ओर रोडोडेंड्रोन वॉटरमार्क
  - o बीच में नेपाल का हल्का हरा मैप
  - o मैप के पास अशोक पिलर जिस पर लिखा है: "लुंबिनी, भगवान बुद्ध का जन्मस्थान।"
- भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, यह दोहराते हुए कि इससे ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती और नेपाल के कदम को भड़काने वाला और एकतरफ़ा बताया।

कालापानी इलाका उत्तराखंड के उत्तर-पश्चिमी कोने में है। इसका नाम काली नदी (नेपाल में महाकाली) के नाम पर रखा गया है, जो भारत और नेपाल के बीच एक नैचुरल बाउंड्री का काम करती है। काली नदी का सोर्स ऐतिहासिक रूप से विवादित रहा है, जो इलाके के झगड़े की जड़ है।

ऐतिहासिक संधि

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि (1816) ने काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा तय की।
- हालांकि, संधि में नदी के सही सोर्स के बारे में नहीं बताया गया था, और बाद के ब्रिटिश मैप में इसके अलग-अलग पॉइंट दिखाए गए थे। नेपाल ने 1998 में भारत के साथ कालापानी का मुद्दा ऑफिशियली उठाया।

विवाद की खास बातें

भारत का स्टैंड

- कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है।
- नदी यहीं से निकलती है, जिससे यह इलाका भारतीय हो जाता है।

Recent Context

- In November 2025, Nepal's government decided to issue Rs 100 currency notes featuring its updated political map, which includes Kalapani, Lipulekh, and Limpiyadhura, areas under India's control.
- The new note features:
  - o Mt Everest on the left
  - o Rhododendron watermark on the right
  - o Faint green map of Nepal at the centre
  - o Ashoka Pillar near the map with the text: "Lumbini, the birthplace of Lord Buddha."
- India reacted sharply, reiterating that this does not change ground realities and calling Nepal's move provocative and unilateral.

The Kalapani region lies in the northwestern corner of Uttarakhand. It is named after the Kali River (Mahakali in Nepal), which acts as a natural boundary between India and Nepal.The source of the Kali River has historically been disputed, forming the core of the territorial disagreement.

Historical Treaty

- The Treaty of Sugauli (1816) between the British East India Company and Nepal established the Kali River as Nepal's western boundary.
- However, the treaty did not specify the exact river source, and subsequent British maps showed varying points of origin. Nepal officially raised the Kalapani issue with India in 1998.

Dispute Overview

India's Stand

- Kalapani is part of Pithoragarh district, Uttarakhand.
- The river originates here, making the territory Indian.

नेपाल का स्टैंड

- दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा या लिपुलेख से निकलती है, जिसमें सुदूरपश्चिम प्रांत के ये इलाके भी शामिल हैं।
- मई 2020 में एक पॉलिटिकल मैप जारी होने और नेपाल की पार्लियामेंट द्वारा इसके समर्थन ने इस दावे को ऑफिशियल बना दिया।

ट्रिगर इवेंट्स

- 2020: भारत ने कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक एक लिंक रोड का उद्घाटन किया।
- नेपाल ने सीमा के मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के लिए 2014 के द्विपक्षीय समझौते का हवाला देते हुए विरोध किया।
- नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मैप अपडेट के कारण भारत-नेपाल कम्युनिकेशन में कुछ समय के लिए रुकावट आई।

स्ट्रेटेजिक असर

- विवादित क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक महत्व है:
  - o चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से नज़दीकी
  - o उत्तराखंड और उत्तरी भारत की सुरक्षा के लिए ज़रूरी
- नेपाल के एकतरफ़ा कदमों से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा होने का खतरा है, हालांकि भारत का कहना है कि बातचीत ही इसका हल है।
- लोगों की फ्री मूवमेंट और बड़ी संख्या में भारतीय-नेपाली डायस्पोरा को देखते हुए, इस मुद्दे को डिप्लोमैटिक तरीके से सुलझाना दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी है।

Nepal's Stand

- Claims the river originates from Limpiyadhura or Lipulekh, including these areas in Sudurpaschim province.
- The release of a political map in May 2020 and its endorsement by Nepal's Parliament formalized the claim.

Trigger Events

- 2020: India inaugurated a link road from Dharchula to Lipulekh Pass for Kailash Mansarovar pilgrims.
- Nepal protested, citing a 2014 bilateral understanding to resolve boundary issues through dialogue.
- Nepal's Constitutional Amendment and map update led to a temporary breakdown in India-Nepal communication.

Strategic Implications

- The disputed region has strategic significance:
  - o Proximity to the Tibet Autonomous Region of China
  - o Important for security of Uttarakhand and northern India
- Nepal's unilateral moves risk straining bilateral ties, although India maintains that dialogue remains the solution.
- Given free movement of people and a large Indian-Nepali diaspora, resolving the issue diplomatically is crucial for both countries.